है, स्थिति संतोषजनक है, फिर भी, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पर्याप्त प्रबन्ध पद्धति की संस्थापना, शैक्षिक सामग्रियों का विकास और अध्यापकों के प्रशिक्षण जैसे इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं में कमियां हैं। सातवीं योजना के अन्त तक 7820 व्यावसायिक कक्षाओं सहित 2478 संस्थाओं में 1.95 लाख छात्रों के वार्षिक दाखिले के लिए सुविधाएं मंजूर की गयी हैं। सामान्य बीमा निगम, जीवन-बीमा निगम, और रेल मंत्रालय से नियोजन सम्बंधों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इन्हें स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण और उद्योग मंत्रालय के साथ अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कुछ अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया गया है। की गयी समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि इसको कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं को कम से कम किया जा सके।

(ग) स्कूल शिक्षा का मोटे-तौर पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, उपरोक्त संदर्भित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को इस कार्यक्रम की कोटि का विस्तार करने और उसमें सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना को और अधिक दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए उन्हें समय-समय पर हिदायतें/मार्गदर्शी रूप-रेखाएं प्रदान की जाती हैं।

महाराष्ट्र के सांगली जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के एकक

21. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सांगली जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त जिले में ऐसे कुछ और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सांगली जिले को एक "पिछड़ा जिला" घोषित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सांगली जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने से सम्बंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोबर्धन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के सांगली जिले में न तो पंजीकृत कार्यालय वाला केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम है और न ही वर्ष 1990-91 के दौरान, वहां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित किए जाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र के सांगली जिले को न तो पिछड़ा जिला ही घोषित किया गया है तथा न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। किसी जिले के पिछड़ेपन की घोषणा योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाती है।

Non-availability of drinking water in KV, R.K. Puram, Andrews Ganj, New Delhi

22. SHRI JAGADISH JANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that drinking water facility is not available for students in all the Kendriya Vidyala-